

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक:- 18.10.2023

अपील संख्या 67/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00117)

1. दामोदर प्रसाद पुत्र गोपालदास जाति सारस्वत निवासी राणीसर बास,
तहसील व जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 14-09-1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर



उपस्थिति:-

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 14-09-1999 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को चक 27 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/42 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा व चक 33 सीडब्ल्यू बी के मुरब्बा नम्बर 127/58 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 05-09-1990 को किया गया था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत तमाम किश्तें खजानाराज में जमा करवा जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का चक 27 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 167/42 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।



उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किश्त बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-09-1999 के विरुद्ध अपील दिनांक

09-03-21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलाट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलाट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-09-1999 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 09-03-2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलाट का आवंटन किशतों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किशतें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 1976 में अपीलाट्स के पिता के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 35 अपीलाट के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार बज्जू के सेल रजिस्टर के अवलोकन पर यह साबित है कि अपीलाट द्वारा दिनांक 14-03-1991 चालान संख्या 99 राशि 56593/-, चालान संख्या 68 दिनांक 19-12-1993 राशि 56593/-, चालान संख्या स्पे. 5 दिनांक 06-05-1995 राशि 56594/-, खजानाराज में जमा करवाई गई। जब किशतें लगातार जमा हो रही थी तो किशतों के अभाव में अपीलाट्स के विधिवत आवंटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 06 साल तक लगातार किशतें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण

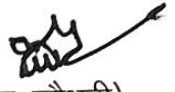


तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-09-1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो, अपीलांट की यदि कोई बकाया राशि हो तो तीन माह में जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.10.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर